



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3268]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 3268]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ASVINA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3584 (अ) .—यतः, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (जिसका इसके पश्चात् इस अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खंड (i), किसी बैंकिंग कंपनी को ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किए जाने पर रोक लगाता है जो किसी ऐसी अन्य कंपनी का निदेशक है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत (क) किसी बैंकिंग कंपनी की अनुपंगी या (ख) पंजीकृत कंपनी न हो;

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खंड (i) के परंतुक में यह उपबंध किया गया है कि उक्त उप-खंड के प्रतिबंध किसी कंपनी के ऐसे निदेशक के संबंध में तीन माह से अनधिक अस्थायी अवधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत ऐसी अवधि, जो नौ माह से अधिक न हो;

और यतः, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री उदय कोटक, प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को उक्त अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत आरंभ में तीन माह की अवधि के लिए और तत्पश्चात् नौ माह की अतिरिक्त अवधि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर बने रहने की अनुमति दी थी और उक्त नौ माह की अतिरिक्त अवधि 2 अक्टूबर, 2019 को समाप्त होगी;

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा 53 भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा करने की शक्ति प्रदान करती है कि उक्त अधिनियम के कोई या सभी उपबंध किसी बैंककारी कंपनी अथवा संस्था अथवा बैंकिंग कंपनी के किसी वर्ग पर सामान्य रूप से अथवा यथा-निर्दिष्ट किसी ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं होंगे;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के लागू होने से छूट प्रदान किए जाने को आवश्यक माना है, जहां तक इसका संबंध श्री उदय कोटक, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड

फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में 3 अक्तूबर, 2019 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करने से है।

अतः अब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के उपबंध, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लागू नहीं होंगे, जहां तक ये कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री उदय कोटक के इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में 2 अक्तूबर, 2020 तक की अवधि के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक होने से संबंधित हैं।

[फा.सं. 7/129/2019-बीओए- I]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2019

S.O. 3584 (E).—Whereas, sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) (hereinafter referred to as the said Act), prohibits a banking company to be managed by any person who is a director of any other company not being (a) a subsidiary of the banking company, or (b) a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

And whereas, the proviso to the said sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act provides that the prohibition in the said sub-clause shall not apply in respect of any such director for a temporary period not exceeding three months or such further period not exceeding nine months as the Reserve Bank of India may allow;

And whereas, the Reserve Bank of India allowed Shri Uday Kotak, Managing Director and Chief Executive Officer of Kotak Mahindra Bank Limited to be on the Board of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited as its Non-executive Director, initially for a period of three months and subsequently for a further period of nine months, under the above provisions of the said Act and the said further period of nine months shall expire on the 2nd day of October, 2019;

And whereas, section 53 of the said Act empowers the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, to declare, by notification in the Official Gazette, that any or all of the provisions of the said Act shall not apply to any banking company or institution or to any class of banking companies either generally or for such period as may be specified;

And whereas, the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, has considered it necessary to grant exemption to Kotak Mahindra Bank Limited from application of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Banking Regulation Act, 1949 in so far as it relates to Shri Uday Kotak, Managing Director and Chief Executive Officer of Kotak Mahindra Bank Limited being on Board of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited as its Non-executive Director, for a further period of one year with effect from the 3rd day of October, 2019.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949, the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Kotak Mahindra Bank Limited in so far as it relates to its Managing Director and Chief Executive Officer Shri Uday Kotak being on Board of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited as its Non-executive Director for a period up to the 2nd day of October, 2020.

[F. No. 7/129/2019-BOA-I]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.